अति आवश्यक

तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 14146/प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 23/10/2023

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल................................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड...................................

विषयः–कार्यभारित स्थापना के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किये जाने न्यायालयीन प्रकरणों में लिमिटेशन एक्ट के तहत पारित निर्णयों के आधार पर प्रतिरक्षण करने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के संज्ञान में ऐसे अनेको न्यायालयीन प्रकरण आये हैं जिनमें सेवारत/सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 को आधार बनाकर कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा उपरांत दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ चाहा जाता है । इस हेतु "के.एल. असरे" एवं "तेजू लाल यादव" प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का सहारा लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त अनेकों कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर म.प्र.शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा परिपत्र क्र./एफ 11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 के माध्यम से नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के समान ही 10,20 एवं 30 वर्ष की सेवा उपरांत तीन समयमान वेतनमानों की भी मांग की जाती रही है। म.प्र.शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से कार्यभारित स्थापना में कर्मचारियों को उक्त लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिये गये हैं किंतु कर्मचारी इन्हें कट ऑफ डेट के स्थान पर नियमित स्थापना हेतु जारी परिपत्र के आधार पर 10,20 या 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के दिनांक से चाह रहे हैं।

अनेकों न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय भी पारित किये गये हैं।

इस कार्यालय द्वारा इस प्रकृति के प्रकरणों का परीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है कि ये सभी प्रकरण सेवाकाल के दौरान प्राप्त होने वाले त्रुटिपूर्ण वेतन से संबंध रखते है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के माध्यम से त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने एवं वेतन एरियर राशि पाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने की समय–सीमा एवं एरियर राशि की पात्रता अवधि के संबंध यह अभिनिर्धारित किया गया है:–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्त होने वाले मामलों में "Cause of action" यानि **''विवाद का कारण''** की समय–सीमा निर्धारित करते हुये कहा गया है कि सेवारत् रहते हुए किसी भी समय माननीय न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने हेतु वाद दायर किया जा सकता है। सेवाकाल समाप्ति उपरांत वाद दायर करने हेतु "Cause of action" उत्पन्न नही होता है। अतः सेवाकाल समाप्ति के उपरांत त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने हेतु वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

(ii) यदि आवेदक का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के समय के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में आवेदक का दावा यदि कोई है जो त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्ति के कारण वेतन एरियर की प्राप्ति से संबंधित है, जिसकी गणना वेतन अंतर की राशि के आधार पर की जाती है तो वह लिमिटेशन एक्ट में दी गई समय–सीमा के अंतर्गत आयेगा और वह एक्ट में प्रावधानित अवधि से अधिक अवधि की एरियर राशि का पात्र नहीं होगा। न्याय दृष्टातों एवं लिमिटेशन एक्ट 1963 में इस हेतु एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष प्रथमतः प्रकरण दायर करने से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की निर्धारित की गयी है ।

संबंधित न्याय दृष्टांतों का विवरण निम्नानुसार है:–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य''** में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 [1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628], सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 **''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह''** में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008

उपरोक्त दोनों निर्णय आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।

परीक्षणानुसार, इस प्रकृति के प्रकरणों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत दायर किये गये प्रकरण समय–बाधित होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है तथा एक सेवारत कर्मचारी के प्रकरण में भी प्रकरण दायर किये जाने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

23/7

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करें। इस प्रकृति के प्रकरणों में निम्नलिखित कार्यवाहियॉ की जाना सुनिश्चित करें :–

1.ऐसे सभी प्रकरणों में जो सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत दायर किये गये है तथा जो वर्तमान में विचाराधीन है, ऊपर उल्लेखित न्यायदृष्टातों को शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में लाते हुवे जबावदावा दाखिल करवाना सुनिशचित करें ताकि इस प्रकृति के प्रकरणो को समयबाधित बताते हुए खारिज कराया जा सकें।

2.ऐसे सभी प्रकरणों में जो सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत दायर किये गये है तथा जिनमें कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुका है किंतु रिव्यू पिटीशन/रिट अपील दायर करने की संभावना शेष है, शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर रिव्यू पिटीशन/रिट अपील दायर करने की कार्यवाही कर पूर्व निर्णय को खारिज करवाने का प्रयास करें।

3.सेवारत कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के विचाराधीन मामलों में भी ऊपर उल्लेखित न्याय दृष्टांतों को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें।

4.सेवानिवृत्त/सेवारत कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के जिन मामलों में न्यायालयीन निर्णय प्राप्त हो चुके है तथा निर्णयों के पालन की अनिवार्यता उत्पन्न हो गयी है उनमें न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में कमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के उपरांत, एरियर राशि स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखे कि कर्मचारी का वेतन कमोन्नत/समयमान वेतनमान के अनुसार काल्पनिक रूप से निर्धारित करते हुए उसे रिट याचिका दायर करने की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की स्वीकृति प्रदान करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार दो निर्णय

23/10

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 14146/प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 23/10/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दो निर्णय

23/10

प्रमुख अभियंता

Kanoon

Mobile View

Premium Members Advanced Search Case Removal

Search

Cites 3 docs
The Administrative Tribunals Act, 1985
S.S. Rathore vs State Of Madhya Pradesh on 6 September, 1989
Thota China Subha Rao vs Mattapalli Raju on 10 May, 1949
Citedby 135 docs - [View All]
Dr.Sobha Jasmine S vs Udham Singh Kamal on 25 July, 2011
Shouvik Kr Parbat vs G S I on 14 September, 2017
Sunil Kumar vs Govt. Of Nctd on 9 January, 2018
Nurul Islam vs The State Of West Bengal & Ors. on 18 May, 2000
Hasmukhbhai vs President on 21 February, 2011

Get this document in PDF Print it on a file/printer Download Court Copy
War on Translation
S Language
Translate

ake notes as you read a judgment using our *Virtual Legal Assistant* and get email alerts whenever a new judgment matches your query (*Query Alert Service*). Try out our *Premium Member services* -- Free for one month.

User Queries
pay fixation
time barred
jagdish saran
recuring cause
continuing wrong

Supreme Court of India

M.R. Gupta vs Union Of India & Ors on 21 August, 1995

Equivalent citations: 1996 AIR 669, 1995 SCC (5) 628

Author: J S Verma

Bench: Verma, Jagdish Saran (J)

```
PETITIONER:
M.R. GUPTA

Vs.

RESPONDENT:
UNION OF INDIA & ORS.

DATE OF JUDGMENT21/08/1995

BENCH:
VERMA, JAGDISH SARAN (J)
BENCH:
VERMA, JAGDISH SARAN (J)
VENKATASWAMI K. (J)

CITATION:
1996 AIR 669 1995 SCC (5) 628
1995 SCALE (5)29

ACT:

HEADNOTE:
```

38 PM
GMENT VERMA. J.

ive granted.

: only question for decision is : Whether the impugned judgment of the Tribunal dismissing as time red the application made by the appellant for proper fixation of his pay is contrary to law? Only a / facts are material for deciding this point.

: appellant joined the service of the State of Punjab as Demonstrator in the Government Polytechnic 1967. Thereafter, he joined service in the railways in 1978. The appellant claimed that the fixation of pay on his joining service in the railways was incorrect and that he was entitled to fixation of his / after adding one increment to the pay which he would have drawn on 1.8.1978 in accordance with le No. 2018 (N.R.S.N. 6447) equivalent to Fundamental Rule 22-c. The representation of the pellant to this effect was rejected before coming into force of the Administrative Tribunals Act, 35. The appellant then filed an application on 4.9.1989 before the Tribunal praying inter alia for per [illegible]tion of his initial pay with effect from 1.8.1978 and certain consequential benefits. The plic. .on was contested by the respondents on the ground that it was time barred since the cause of ion had arisen at the time of the initial fixation of his pay in 1978 or latest on rejection of his resentation before coming into force of the Administrative Tribunals Act, 1985. The subsequent resentations made by the appellant for proper fixation of his pay were alleged to be immaterial for s purpose.

e Tribunal has upheld the respondents' objection based on the ground of limitation. It has been held it the appellant had been expressly told by the order dated 12.8.1985 and by another letter dated 3.1987 that his pay had been correctly fixed so that he should have assailed that order at that time hich was one time action". The Tribunal held that the raising of this matter after lapse of 11 years ice the initial pay fixation in 1978 was hopelessly barred by time. Accordingly, the application was smissed as time barred without going into the merits of the appellant's claim for proper pay fixation.

iving heard both sides, we are satisfied that the Tribunal has missed the real point and overlooked the ux of the matter. The appellant's grievance that his pay fixation was not in accordance with the rules, is the assertion of a continuing wrong against him which gave rise to a recurring cause of action each ne he was paid a salary which was not computed in accordance with the rules. So long as the pellant is in service, a fresh cause of action arises every month when he is paid his monthly salary on e [illegible]is of a wrong computation made contrary to rules. It is no doubt true that if the appellant's claim found correct on merits, he would be entitled to be paid according to the properly fixed pay scale in e future and the question of limitation would arise for recovery of the arrears for the past period. In her words, the appellant's claim, if any, for recovery of arrears calculated on the basis of difference in e pay which has become time barred would not be recoverable, but he would be entitled to proper xation of his pay in accordance with rules and to cessation of a continuing wrong if on merits his aim is justified. Similarly, any other consequential relief claimed by him, such as, promotion etc. ould also be subject to the defence of laches etc. to disentitle him to those reliefs. The pay fixation in be made only on the basis of the situation existing on 1.8.1978 without taking into account any ther consequential relief which may be barred by his laches and the bar of limitation. It is to this mited extent of proper pay fixation the application cannot be treated as time barred since it is based n a recurring cause of action.

he Tribunal misdirected itself when it treated the appellant's claim as 'one time action' meaning iereby that it was not a continuing wrong based on a recurring cause of action. The claim to be paid ie correct salary computed on the basis of proper pay fixation, is a right which subsists during the ntire tenure of service and can be exercised at the time of each payment of the salary when the mployee is entitled to salary computed correctly in accordance with the rules. This right of a overnment servant to be paid the correct salary throughout his tenure according to computation made [illegible]ordance with rules, is akin to the right of redemption which is an incident of a subsisting [illegible] and subsists so long as the mortgage itself subsists, unless the equity of redemption is [illegible] [illegible]

ned counsel for the respondents placed strong reliance on the decision of this Court in S.S. ore vs. State of Madhya Pradesh, [1989] Supp. 1 SCR 43. That decision has no application in the ent case. That was a case of termination of service and, therefore, a case of one time action, unlike claim for payment of correct salary according to the rules throughout the service giving rise to a h cause of action each time the salary was incorrectly computed and paid. No further consideration at decision is required to indicate its inapplicability in the present case.

the aforesaid reasons, this appeal has to be allowed. We make it clear that the merits of the ellant's claim have to be examined and the only point concluded by this decision is the one decided ve. The question of limitation with regard to the consequential and other reliefs including the ars, if any, has to be considered and decided in accordance with law in due course by the Tribunal. matter is remitted to the Tribunal for consideration of the application and its decision afresh on its in accordance with law. No costs.

Supreme Court of India
Union Of India & Anr vs Tarsem Singh on 13 August, 2008
Author: R.V.Raveendran
Bench: R.V. Raveendran, Lokeshwar Singh Panta

1

Reportable

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.5151-5152 OF 2008
(Arising out of SLP [C] Nos.3820-3821 of 2008)

Union of India & Ors. ... Appellants

Vs.

Tarsem Singh ... Respondent

ORDER

R.V.RAVEENDRAN, J.

Leave granted. Heard learned counsel for the parties.

2. The respondent while working in the Indian Army was invalidated out of Army service, in medical category, on 13.11.1983. He approached the High Court in 1999 seeking a direction to the appellants to pay him disability pension. A learned Single Judge by order dated 6.12.2000 allowed the writ petition and directed the appellants to grant him disability pension at the rates permissible. In so far as arrears, the relief was restricted to 38 months prior to the filing of the writ petition. The respondent was also directed to appear before the Re-survey Medical Board as and when called upon by the appellants. The appellants did not contest the said decision and granted disability pension to respondents and also released the arrears of disability pension for 38 months.

3. The respondent however was not satisfied. According to him the disability pension ought to be paid from the date it fell due on 13.11.1983. He therefore filed a Letters Patent Appeal. The said appeal was allowed by the Division Bench of the High Court by judgment dated 6.12.2006. The Division Bench held that the respondent was entitled to disability pension from the date it fell due, and it should not be restricted to a period of three years and two months prior to the filing of the writ petition. By a subsequent modification order dated 23.2.2007, the Division Bench also granted interest on the arrears at the rate of 6% per annum. The said judgment and order of the Division Bench is challenged in this appeal. The only question that therefore arises for our consideration is

whether the High Court was justified in directing payment of arrears for a period of 16 years instead of restricting it to three years.

4. The principles underlying continuing wrongs and recurring/ successive wrongs have been applied to service law disputes. A `continuing wrong' refers to a single wrongful act which causes a continuing injury. `Recurring/successive wrongs' are those which occur periodically, each wrong giving rise to a distinct and separate cause of action. This Court in Balakrishna S.P. Waghmare vs. Shree Dhyaneshwar Maharaj Sansthan - [AIR 1959 SC 798], explained the concept of continuing wrong (in the context of section 23 of Limitation Act, 1908 corresponding to section 22 of Limitation Act, 1963) :

> "It is the very essence of a continuing wrong that it is an act which creates a continuing source of injury and renders the doer of the act responsible and liable for the continuance of the said injury. If the wrongful act causes an injury which is complete, there is no continuing wrong even though the damage resulting from the act may continue. If, however, a wrongful act is of such a character that the injury caused by it itself continues, then the act constitutes a continuing wrong. In this connection, it is necessary to draw a distinction between the injury caused by the wrongful act and what may be described as the effect of the said injury."

In M. R. Gupta vs. Union of India [1995 (5) SCC 628], the appellant approached the High Court in 1989 with a grievance in regard to his initial pay fixation with effect from 1.8.1978. The claim was rejected as it was raised after 11 years. This Court applied the principles of continuing wrong and recurring wrongs and reversed the decision. This Court held :

> "The appellant's grievance that his pay fixation was not in accordance with the rules, was the assertion of a continuing wrong against him which gave rise to a recurring cause of action each time he was paid a salary which was not computed in accordance with the rules. So long as the appellant is in service, a fresh cause of action arises every month when he is paid his monthly salary on the basis of a wrong computation made contrary to rules. It is no doubt true that if the appellant's claim is found correct on merits, he would be entitled to be paid according to the properly fixed pay scale in the future and the question of limitation would arise for recovery of the arrears for the past period. In other words, the appellant's claim, if any, for recovery of arrears calculated on the basis of difference in the pay which has become time barred would not be recoverable, but he would be entitled to proper fixation of his pay in accordance with rules and to cessation of a continuing wrong if on merits his claim is justified. Similarly, any other consequential relief claimed by him, such as, promotion etc., would also be subject to the defence of laches etc. to disentitle him to those reliefs. The pay fixation can be made only on the basis of the situation existing on 1.8.1978 without taking into account any other consequential relief which may be barred by his laches and the bar of limitation. It is to this limited extent of proper pay fixation, the application cannot be treated as time barred........"

In Shiv Dass vs. Union of India - 2007 (9) SCC 274, this Court held:

> "The High Court does not ordinarily permit a belated resort to the extraordinary remedy because it is likely to cause confusion and public inconvenience and bring in its train new injustices, and if writ jurisdiction is exercised after unreasonable delay, it may have the effect of inflicting not only hardship and inconvenience but also injustice on third parties. It was pointed out that when writ jurisdiction is invoked, unexplained delay coupled with the creation of third party rights in the meantime is an important factor which also weighs with the High Court in deciding whether or not to exercise such jurisdiction.
>
> In the case of pension the cause of action actually continues from month to month. That, however, cannot be a ground to overlook delay in filing the petition.......... If petition is filed beyond a reasonable period say three years normally the Court would reject the same or restrict the relief which could be granted to a reasonable period of about three years."

5. To summarise, normally, a belated service related claim will be rejected on the ground of delay and laches (where remedy is sought by filing a writ petition) or limitation (where remedy is sought by an application to the Administrative Tribunal). One of the exceptions to the said rule is cases relating to a continuing wrong. Where a service related claim is based on a continuing wrong, relief can be granted even if there is a long delay in seeking remedy, with reference to the date on which the continuing wrong commenced, if such continuing wrong creates a continuing source of injury. But there is an exception to the exception. If the grievance is in respect of any order or administrative decision which related to or affected several others also, and if the re-opening of the issue would affect the settled rights of third parties, then the claim will not be entertained. For example, if the issue relates to payment or re-fixation of pay or pension, relief may be granted in spite of delay as it does not affect the rights of third parties. But if the claim involved issues relating to seniority or promotion etc., affecting others, delay would render the claim stale and doctrine of laches/limitation will be applied. In so far as the consequential relief of recovery of arrears for a past period, the principles relating to recurring/successive wrongs will apply. As a consequence, High Courts will restrict the consequential relief relating to arrears normally to a period of three years prior to the date of filing of the writ petition.

6. In this case, the delay of 16 years would affect the consequential claim for arrears. The High Court was not justified in directing payment of arrears relating to 16 years, and that too with interest. It ought to have restricted the relief relating to arrears to only three years before the date of writ petition, or from the date of demand to date of [illegible] whichever was lesser. It ought not to have granted interest on arrears in such circumstances.

7. In view of the above, these appeals are allowed. The order of the Division Bench directing payment of disability pension from the date it fell due, is set aside. As a consequence, the order of the learned Single Judge is restored.

...................................J [R. V. Raveendran] ....J [Lokeshwar Singh Panta] New Delhi;

August 13, 2008.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999
19.4.1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

::=::

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में, प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय ।

2/ राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है ।

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परंतु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है ।

यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो ।

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा ।

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा ।

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही कार्य कर रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो।"

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3/- यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे ।

4/- उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा ।

5/- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/नि0/चार, दिनांक 19.4.1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)
(एम0के0 वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमोन्नत वेतनमान के लिये वेतनमानों की सूची

क्रमांक	वेतनमान	क्रमोन्नति पर देय वेतनमान
1.	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540
2.	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
3.	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590
4.	3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200
5.	3500-80-4700-100-5200	4000-100-6000
6.	4000-100-6000	4500-125-7000
7.	4500-125-7000	5000-150-8000
8.	5000-150-8000	5500-175-9000
9.	5500-175-9000	6500-200-10500
10.	6500-200-10500	7500-250-12000
11.	7500-250-12000	8000-275-13500
12.	8000-275-13500	10000-325-15200
13.	10000-325-15200	*10650-325-15850

* यह वेतनमान भारत सरकार के वेतनमानों में शामिल है, परन्तु राज्य शासन के वेतनमानों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है । अतः क्रमोन्नति अंतर्गत यह वेतनमान स्वीकृत होगा ।

पृष्ठांकन क्र. [illegible]/1/1/आप्र/99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999
19.4.1999

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर.
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल.
सचिव, वित्त की ओर महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु
2. सचिव, विधानसभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
3. माननीय मुख्य मंत्रीजी/मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ.
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित।
13. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99 — भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 1999 / 12 अक्टूबर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।
संदर्भ:- सा0प्र0वि0 का ज्ञाप क्र. एफ. 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.3.99/19.4.99.

::=::

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 17.3.99/19.4.99 के द्वारा लागू की थी। इन निर्देशों की कंडिका-3 में यह शर्त थी कि ये आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे।

2/- राज्य शासन ने पूर्ण विचारोपरांत उक्त शर्त को विलोपित करने का निर्णय लिया है। ये आदेश दिनांक 19.4.99 से ही प्रभावशील होंगे ।

3/- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1878/3279/99/सी/चार, दिनांक 12.10.99 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 3.5.2000
17.5.2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना ।
संदर्भ :-इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 17.3.99/19.4.99 तथा 25.9.99/12.10.99.

राज्य शासन ने इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दि0-17.3.99/19.4.99 द्वारा शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना लागू करने सम्बंधी निर्देश जारी किए थे ।

2/ विभिन्न कर्मचारी संघों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शासकीय सेवा में प्रथम नियमित नियुक्ति से एक ही वेतनमान में (तत्स्थानी वेतनमान सहित) 24 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के लाभ के लिए राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापनदिनांक 17.3.99/19.4.99 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

संशोधन

1. उपरोक्त ज्ञापन में कंडिका 2 के पश्चात् कंडिका 2-ए निम्नानुसार जोडी जाती है :-

"2-ए- ऐसे शासकीय सेवक जिनको नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू प्रारम्भिक वेतनमान अथवा उसके ——————

निरंतर.....2/

तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त अन्य वेतनमान/पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अग्रेषण करके अथवा अन्य किसी माध्यम से नहीं मिला हो तो उन्हें संलग्न सूची के कॉलम (4) में दर्शाए वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान जो भी लागू हो देय होंगे।"

2/ उपरोक्त ज्ञापन की कंडिका 4 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है.–

"उपरोक्त कंडिका –2 एवं 2–ए" में दर्शाए अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 अथवा 4 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा."

3/ उपरोक्त ज्ञापन के संलग्न सूची के स्थान पर इस ज्ञापन के संलग्न सूची प्रतिस्थापित की जाती है ।

4/ ये आदेश दिनांक 19.4.99 से ही प्रभावशील होंगे ।

5/ ये आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1035/1036/1428/सी/चार, दिनांक 17.5.2000 द्वारा महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर) 24-5-2000
(एस०व्ही०ग्वालियरकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/1999 भोपाल, दिनांक 3 मई, 2000 / 17 मई, 2000

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, म.प्र. विधानसभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, जबलपुर.

निरंतर.....पेज 3 पर

[illegible]

क्र.	वेतनमान	क्रमोन्नत पद के वेतनमान	कंडिका-2-ए के प्रकरणों में देय वेतनमान
1.	2.	3.	4.
1.	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
2.	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590
3.	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200
4.	3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200	4000-100-6000
5.	3500-80-4700-100-5200	4000-100-6000	4500-125-7000
6.	4000-100-6000	4500-125-7000	5000-150-8000
7.	4500-125-7000	5000-150-8000	5500-175-9000
8.	5000-150-8000	5500-175-9000	6500-200-10500
9.	5500-175-9000	6500-200-10500	7500-250-12000
10.	6500-200-10500	7500-250-12000	8000-275-13500
11.	7500-250-12000	8000-275-13500	10000-325-15200
12.	8000-275-13500	10000-325-15200	10650-325-15850
13.	10000-325-15200	10650-325-15850	12000-375-16500

16

ANNEXURE

Ann-R/3

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ-5-4/1/वेआप्र/98

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2001
29 मार्च, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- 1. शासकीय वाहन चालकों के लिए क्रमोन्नति योजना।
2. कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि सेवा से नियमित स्थापना में नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण।

संदर्भ :- 1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 1792/98/सी/चार, दिनांक 18.9.1998 एवं 800-ए/4272/99/सी/चार, दिनांक 13.4.2000
2. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ. 1-1/वेआप्र/99 17.3.99/19.4.99, 25.9.99/12.10.99 एवं 5.5.2000/17.5.2000.

::=::

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 18.9.1998 द्वारा वाहन चालकों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था जो ज्ञाप की (1) से (7) की शर्तों के आधार पर देय था। ज्ञाप की शर्त क्रमांक (2) में क्रमोन्नति वेतनमान 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमित वाहन चालकों को देय था तथा शर्त क्रमांक (3) में वेतनमान "कार्यभारित आकस्मिकता से वेतन पाने वाले वाहन चालकों" को 15 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत देय था।

2- राज्य शासन ने इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दि. 17.3.99/19.4.99 द्वारा शासन की नई "क्रमोन्नति योजना" लागू की है जिसमें प्रत्येक नियमित कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में, प्रवेश के

निरंतर....2 पर

TRUE COPY
Dr. Anuvad Shrivastava

{2}

...मान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ ...त शर्तों के अध्यधीन देय है ।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.9.98 एवं ...शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.3.99/19.4.99 ...र भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग के संदर्भित ...ंक 18.9.98 में संशोधन कर राज्य शासन ने वित्त विभाग के ...प दिनांक 13.4.2000 द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित ... :-

{क} वित्त विभाग के आदेश दि. 18.9.98 नियमित पदस्थापना में कार्यरत वाहन चालकों को लागू नहीं होंगे । नियमित स्थापना में कार्यरत वाहन चालकों को क्रमोन्नति वेतनमान की सुविधा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.3.99/19.4.99 के अनुसार प्राप्त होगी ।

{ख} वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.9.98 सिर्फ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों को लागू होंगे ।

4. शासकीय वाहन चालक/यांत्रिकी कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 17.3.99/19.4.99 द्वारा लागू की गई क्रमोन्नति योजना का लाभ उपर्युक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन नियमित स्थापना के वाहन चालकों के समान "कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि वाहन चालकों" को भी प्राप्त होगा। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 17.5.2000/19.5.2000 के तारतम्य में दिनांक 25.9.99/12.10.99 एवं दिनांक 3.5.2000/17.5.2000 को जारी निर्देशों में निहित प्रावधान भी नियमित स्थापना और कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों को भी समान रूप से लागू होंगे ।

TRUE COPY
Dr. Anuvad Shrivastava
Advocate

राज्य शासन ने वाहन चालकों के संबंध में क्रमोन्नति योजना लागू किए जाने के विषय में निम्नानुसार निर्णय भी लिए हैं :-

(अ) कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा से नियमित सेवा में आए हुए वाहन चालकों के संबंध में 12 वर्षों/ 24 वर्षों की सेवावधि की गणना दोनों सेवाओं की सेवावधि को जोड़कर की जावे।

(ब) कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों को भी नियमित कर्मचारियों के समान 12 वर्ष/24वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमोन्नति योजना का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों में निहित शर्तों के अध्यधीन दिया जाए।

6. ये आदेश दिनांक 19.4.1999 से ही प्रभावशील होंगे।

7. वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 18.9.98 एवं 13.4.2000 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

8. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमित स्थापना/सेवा में नियुक्ति होने पर उन्हें नियमित स्थापना/सेवा के पद पर वेतन निर्धारण के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि सेवा के पद में प्राप्त वेतन का संरक्षण दिया जावेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 688/854/2001/ सी-चार- दिनांक 29.03.2001 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

26/3/01

सामान्य प्रशासन विभाग.

निरंतर... पेज 4 पर

TRUE COPY
Anuvad Shrivastava
Advocate

20

4

19

148

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2001
29 मार्च, 2001

...1/विआप/98

... भारत के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
... सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/राज्यमंत्री, म. प्र. शासन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
इन्दौर/ग्वालियर.
महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल.
अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल
प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग. —
आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,
म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
16. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
17. कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर अतिरिक्त प्रतियां मान्यता प्राप्त
18. संगठनों को प्रेषित करने हेतु ।

को आगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(हस्ताक्षर)
(वाय. एस. बेले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

TRUE COPY
(signature)
Dr. Anuvad Shrivastava
Advocate

22

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन— मंत्रालय—भोपाल

क्रमांक / एफ.11 / 1 / 2008 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2008
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषयः— मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–1 / 1 / वे.आ.प्र. / 99 दिनांक 17 मार्च, 1999 / 19.4.1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17–5–2000

—0—

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील कमोन्नति योजना को संशोधित करते हुये समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है ।

2. सिविल सेवाओं में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ" तथा "ब" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा । सीधी भर्ती से तात्पर्य संवर्ग में स्वीकृत पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार प्रतियोगी एवं विभागीय परीक्षा में जो सभी के लिये समान रूप से खुली हैं, के अनुसार भर्ती से हैं । ऐसी सीमित विभागीय चयन परीक्षा जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हों, के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं ऐसी नियुक्ति के दिनांक से इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान की पात्रता हेतु गणना की जाएगी ।

3. यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है ।

4. इस योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं। यदि सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत जिस संवर्ग में पदोन्नति होती है उसका वेतनमान इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उच्चतर वेतनमान से भी उच्चतर है तो सीधी भर्ती वाले संवर्ग का श्रेणीकरण कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, तथा प्रवर श्रेणी जैसा उपयुक्त हो, में किया जायेगा। यदि इस योजनान्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान पदोन्नत संवर्ग के वेतनमान से उच्चतर है, तो इस योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाला उच्चतर वेतनमान व्यक्तिगत वेतन के रूप में ही देय होगा और इसके लिये सेवा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती वाले संवर्ग का पृथक से श्रेणीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा इस संशोधित योजना अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान, जैसा लागू हो, का लाभ 1.4.2006 से प्राप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–1 / 1 / वे.आ.प्र. / 99 दिनांक 17 मार्च, 1999 / 19.4.1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17–5–2000, के अनुसार कमोन्नत वेतनमानों के अंतर्गत प्राप्त लाभ संबंधी प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2–6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुये, इस योजना का लाभ दिनांक 1–4–2006 से दिया जायेगा ।

7. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त हैं, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभ दायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजनांतर्गत नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् भी व्यक्तिगत वेतन के रूप में करेगा ।

8. यदि इस योजना अन्तर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान में नियुक्त रहते हुये कोई शासकीय सेवक उसी वेतनमान में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता प्रथम उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से होगी ।

9. दिनांक 1.4.2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1–4–2006 से होगी। दिनांक 1–4–2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है तो उसे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

10. यदि किसी शासकीय सेवक की दिनांक 1–4–2006 को प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि से अधिक सेवा अवधि है तो अधिक सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये गणना में ली जायेगी। उदाहरणार्थ यदि प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये 8 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है और दिनांक 1–4–2006 को उसकी कुल सेवा अवधि 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो शेष 4 वर्ष की अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान हेतु गणना में ली जायेगी अर्थात जिस भी दिनांक को उसकी सेवा अवधि 16 वर्ष हो जाती है उस दिनांक से उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2–6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुये, इस योजना का लाभ दिनांक 1–4–2006 से दिया जायेगा, उनके मामलों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वेतनमान में शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जायेगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए (i) के अंतर्गत नहीं होगा ।

12. यदि किसी शासकीय सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के सन्दर्भ में अंकित परिपत्रों के द्वारा लागू क्रमोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामलों में इस परिपत्र के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्ता के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होगें ।

13. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा। परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

14. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ–1–1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19 अप्रैल, 99 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 17–5–2000 में दर्शित प्रावधानों को इस सीमा तक संशोधित माना जाए ।

15. विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट–1 के अनुसार उच्चतर वेतनमान का प्रावधान किया जाएगा । इस परिपत्र के परिशिष्ट–2 में उल्लेखित विभिन्न विभागों के विभिन्न संवर्गों को प्रत्येक के सामने अंकित किये अनुसार उच्चतर वेतनमानों की पात्रता इसी परिपत्र के अनुसार होगी । परिशिष्ट–2 में जिन विभागों / संवर्गों का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में, प्रचलित कमोन्नति योजना में संशोधन / प्राप्त प्रस्तावों / मांगों पर विचार किए जाने हेतु प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के प्रकाश में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

16. इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन कर शासकीय कर्मचारी को भुगतान किया जावे । उच्चतर वेतनामनों में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जाँच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए । सभी विभागों में पदस्थ मध्यप्रदेश वित्त सेवा के उपसंचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी भी इन प्रकरणों की जाँच हेतु अधिकृत किए जाते हैं ।

17. समस्त विभाग इन निर्देशों के प्रकाश में उनके द्वारा प्रशासित सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान / संशोधन करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(ए0 पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2008

पृष्ठा.कमांक/एफ.11/1/2008/नियम/चार,
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष.–3),मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन, मंडी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष – लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(पी0सी0 वर्मा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान

क्रमांक	वर्ग	प्रारम्भिक वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतनमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	वर्ग-अ	10000 – 15200	12000–16500	14300–18300
2	वर्ग-ब	8000 – 13500	10000–15200	12000–16500
3		6500 –10500	8000–13500	10000–15200
4	वर्ग-स	5500 – 9000 एवं 5000 – 8000	6500 – 10500	8000 –13500
5		4500 – 7000	5500 – 9000	6500 – 10500
6		4000 – 6000	4500 – 7000	5000 – 8000
7		3500 – 5200 एवं 3050 – 4590	4000–6000	4500 –7000

बी० के० सक्सेना
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग

परिशिष्ट-2

विभागवार एवं संवर्गवार उच्चतर वेतनमानों की सूची

Sr.	Deptt.	HOD	Cadre	Pay Scale before 01.04.06	Present Pay Scale	Pay scale after first upgradation	Pay scale after second upgradation
1	2	3	4	5	6	7	8
	AGRICULTURE						
1		THE DIRECTORATE OF AGRICULTURE	Surveyors	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
2			Statistical Investigator	3500-5200	4500-7000	5500-9000	6500-10500
3			Rural Agri. Extension Officer	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
4			Agriculture Development Officer	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
5			Draughtsman	5000-8000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
6			Senior Agriculture Development Officer	5000-8000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
7			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
8		THE DIRECTORATE OF HORTICULTURE	Rural Hort. Dev. Officer	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
9			Hort .Development Officer	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
10			Senior Hort. Dev. Officer	5000-8000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
11			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
12		THE DIRECTORATE OF AGRICULTURAL	Surveyor	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
13			Patwari	4500-7000	3500-5200	4000-6000	4500-7000
14			Asstt. Engineer.	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	COMMERCE INDUSTRIES						
15		DIRECTORATE OF INDUSTRIES	Asstt. Manager	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
16			Asstt. Director Industry	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
17			Dy. Director Industry	10000-15200	10000-15200	12000-16500	14300-18300
18		INSPECTORATE OF BOILERS	Boiler Inspector Grade-II	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
19		REGISTRAR FIRMS & SOCIETIES	Inspector	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
20			Asstt. Registrar	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	COMMERCIAL TAX						
21		COMMISSIONER COMMERCIAL TAX	Commercial Tax Inspector	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
22			Commercial Tax Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
23		COMMISSIONER EXCISE	Sub Inspector	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500

1	2	3.	4.	5	6	7	8
24			District Excise Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
25		INSPECTOR GENERAL REGISTRATIONS	Sub Registrar	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
			District Registrar	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	COOPERATION						
26		REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES	Cooperative Inspector	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
			Asstt. Registrar	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
27							
	CULTURE						
		DIRECORATE OF OFFICIAL LANGUAGE & CULTURE					
			Junior Instructor	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
28			Asstt. Lecturer	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
29							
	ENERGY						
	FINANCE						
30		THE DIRECTORATE OF TREASURIES, ACCOUNTS & PENSION	Assistant Accounts Officer	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
			Asstt. Programmer	5000-8000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
31			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
32			Programmer	8000-13500	6500-10500	8000-13500	10000-15200
33		THE DIRECTORATE OF LOCAL FUND AUDIT	Junior Auditor	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
34							
			Senior Auditor	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
35			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
36		DIRECTOR SMALL SAVINGS LOTTERIES	Field Asstt.	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
37			Distt. Small Saving Officer	5000-8000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
38		DIRECTOR INSTITUTIONAL FINANCE	Asstt. Programmer	5000-8000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
39							
	FISHERIES						
40		THE DIRECTORATE OF FISHERIES	Fisheries Inspector	3500-5200	4500-7000	5500-9000	6500-10500
			Investigator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
41			Asst.Draughtsman	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
42							
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER PROTECTION			Asstt. Food Inspector	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
43		DIRECTORATE OF FOOD, CIVIL SUPPLIES &	Food Inspector	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
44			Food Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
45			Inspector Weights & Measures	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
46		CONTROLLER, WEIGHTS AND MEASURES	Asstt. Controller	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
47							
	FOREST		Ranger	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
48		DIRECTOR GENERAL FOREST					

28

1	2	3	4	5	6	7	8
	GAD						
49		ACADEMY OF ADMINISTRATION	Asstt. Librarian	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
	HOME						
50		DIRECTOR GENERAL OF POLICE	Sub Inspector	4500-7000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
51			Subedar	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
52			Platoon Commander	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
53			Distt. Commandant	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
54		Directorate of Public Prosecution	Asstt Public Prosecution Officer	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
55		DIRECTOR MEDICOLEGAL INSTITUTE	Medical Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
56		DIRECTOR FORENSIC SCIENCE	Sub Inspector (Photo Grapher)	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
57			Scientific Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	JAIL						
58		INSPECTOR GENERAL OF PRISONS					
59			Dy. Jailor	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
60			Superintendent District Jail	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	TOWN& COUNTRY PLANNING						
61		DIRECTOR TOWN& COUNTRY PLANNING	Asstt. Draughtsman	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
62			Investigator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
63			Town Planning Inspector	5000-8000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
64			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	LABOUR						
65		THE DIRECTORATE, LABOUR COMMISSIONER	Labour Sub Inspector	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
66			Data Entry Operator	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
67			Labour Inspector	4500-7000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
68			Asstt. Labour Officer	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
69			Labour Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
70			Asstt. Director Industial Health	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
71		THE DIRECTORATE, EMPLOYMENT & TRAINING	Emploment Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
72		THE DIRECTORATE, EMPLOYEES STATE	Junior Radiographer	3500-5200	4500-7000	5500-9000	6500-10500
73			Staff Nurse	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
74			Dental Surgeon	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
75			Medical Officer Grade 11	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
76			Ayurvedic Medical Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500

29

1	2	3	4	5	6	7	8
77			Medical Specialist	10000-15200	10000-15200	12000-16500	14300-18300
78	LAW	THE LAW DEPARTMENT	Asstt. Librarian	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
79			Translator	4500-7000	5000-8000	6500-10500	8000-13500
80	ECONOMICS & STATISTICS	THE DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS	Investigator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
81			Asstt. Statistical Officer	5500-9000	6500-9000	6500-10500	8000-13500
82			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
83			Dy. Director	10000-15200	10000-15200	12000-16500	14300-18300
84	PANCHAYAT & SOCIAL WELFARE	DEVELOPMENT COMMISSIONER	Addl. Asstt. Development Commissioner	6500-10500	6500-10500	8000-13500	10000-15200
85	PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE	DIRECORATE OF PUBLIC HEALTH & FAMILY	Lab Technician	3500-5200	4500-7000	5500-9000	6500-10500
86			Staff Nurse	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
87			Opthalmic Asstt.	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
88			Statistical Investigator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
89			Block Extension Educator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
90			Nursing Sister	4500-7000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
91			Sister Tutor	4500-7000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
92		CONTROLLER ,FOOD & DRUGS ADMINISTRATION	Food Inspector	4500-7000	4000-7000	5500-9000	6500-10500
93			Drug Inspector	4500-7000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
94	ECONOMICS & STATISTICS	THE DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS	Investigator	4000-6000	4500-7000	5500-9000	6500-10500
95			Asstt. Statistical Officer	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
96			Asstt. Director	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
97			Dy. Director	10000-15200	10000-15200	12000-16500	14300-18300
98	TRIBAL WELFARE	DIRECTORATE OF TRIBAL WELFARE	District Organiser	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
99			Area Organiser	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500
100	VIDHAN SABHA	VIDHAN SABHA	Reporter	6500-10500	6500-10500	8000-13500	10000-15200
101	VETERINARY	DIRECTORATE OF VETERINARY	Veterinary Asstt. Surgeon	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
102	WOMEN & CHILD DEVELOPMENT	DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT	Supervisors,ICDS	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
103			Project Officer ICDS	5500-9000	5500-9000	6500-10500	8000-13500

30

1	2	3	4	5	6	7	8
104			Distt. Women & Childran Welfare Officer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
105	WATER RESOURCES DEPARTEMENT	ENGINEER-IN-CHIEF, WATER RESOURCES DEPARTEMENT	Asstt. Draughtsman	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
106			Asstt. Engineer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
107	PUBLIC WORKS DEPARTEMENT	ENGINEER-IN-CHIEF,PUBLIC WORKS	Asstt.Draughtsman	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
108			Asstt. Engineer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
109	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTEMENT	ENGINEER-IN-CHIEF,PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTEMENT	Hand Pump Mechanic	3500-5200	3500-5200	4000-6000	4500-7000
110			Asstt. Draughtsman	4000-6000	4000-6000	4500-7000	5000-8000
111			Asstt. Engineer	8000-13500	8000-13500	10000-15200	12000-16500
	BS-post-01/221207						

बी० के० सक्सेना
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग

शाकेमुभो—1695—असविविभो—28-1-08—1000.

(30)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-17/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- **राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में - तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay) ।**

संदर्भ- **वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008.**

-◆-

संदर्भित परिपत्र द्वारा लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान उपलब्ध कराए जायें । अतः वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के अनुसार प्रभावशील समयमान योजना को विस्तारित करते हुये तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है ।

2/ **राज्य की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ", "ब" एवं "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात् ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 1-7-2014** अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी । शासकीय सेवक की तीसरे समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी ।

3/ राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजनान्तर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान

की पात्रता होगी परन्तु ऐसे संवर्गों का तृतीय [illegible] के लिए [illegible]
पृथक से प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे ।

4/ राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को जिनके मूल पद के वेतनमान का उन्नयन दिनांक 1-4-2006 एवं इसके पश्चात् किया गया है, की तृतीय समयमान वेतन की पात्रता के लिए संशोधित वेतनमान में पूर्व नियुक्ति तिथि से काल्पनिक नियुक्ति मानी जाएगी ।

5/ विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन देय होगा । किसी संवर्ग को तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के तुल्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन पूर्व (द्वितीय समयमान वेतन. आदि) से उपलब्ध होने की स्थिति में तृतीय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के निर्धारण के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए ।

6/ मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं इसके क्रम में जारी निर्देशों की अन्य शर्तें तथा प्रक्रियाएं यथास्थिति लागू रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

SUNITA/[illegible]
[illegible]

33

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत देय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन

वर्ग – अ

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
1	15600–39100+6600	37400–67000+8900

वर्ग – ब

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
2	15600–39100+5400	37400–67000+8700
3	9300–34800+4200	15600–39100+7600

वर्ग – स

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
4	9300–34800+3600	15600–39100+6600
5	9300–34800+3200	15600–39100+6600
6	5200–20200+2800	15600–39100+5400
7	5200–20200+2400	9300–34800+4200
8	5200–20200+2100	9300–34800+3200
9	5200–20200+1900	9300–34800+3200

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा क्रमांक : एफ 11-17/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासंन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

34

35

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ–11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21-09-2016
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :– कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2016 से समयमान वेतनमान लागू किये जाने बाबत।

***

राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिये वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी 2008 से जारी प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान योजना तथा म0प्र0शासन, वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ–11–17/ 2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिये जारी तृतीय समयमान वेतनमान योजना राज्य मे कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावशील की जाती है।

2. राज्य की सिविल सेवाओं के लिये समयमान वेतनमान योजना अंतर्गत जारी समस्त नियम एवं निर्देश यथावत लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-95

पृष्ठ.कमांक एफ–11–13/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21-09-2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार,म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र.भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
22. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2,मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-96

36 37

22

Annexure

16

Copy of order sheet

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE A.K.SHRIVASTAVA

WRIT PETITION (S) NO.1070 OF 2003

K.L.Asre, aged 59 years,
son of late Shri Laxman Rao Asre,
Sthal Sahayak (Time Keeper),
Distt. Court (Collectorate) Section,
O/O. S.D.O., P.W.D. (B/R) H.Q. Sub Dn. No.2,
Jabalpur
R/o 2299, in front of Home Guard Darikhana,
Jabalpur. .... PETITIONER

-Versus-

1. State of Madhya Pradesh through the Secretary, Government of M.P. Public Works Department, Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)

2. The Engineer-in-Chief, Public Works Department, M.P. Satpuda Bhawan, Bhopal, M.P.

RESPONDENTS

Shri Ramesh Shrivastava, Advocate for petitioner.
Shri Harish Agnihotri, Govt. Advocate for respondents.

ORDER
(7/11/2005)

By this petition under Articles 226 and 227 of the Constitution of India, the petitioner is seeking the following reliefs :

SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

शपथ आयुक्त
1789

38

-17 23

(a) This Hon'ble Court may kindly be pleased to call for the relevant records from the respondents, examine the same.

(b) To command the respondents to promote the petitioner on the post of Sub Engineer or in the alternative to any suitable post from due date since when others have been granted the same.

(c) To declare that the petitioner is entitled for Krammonati from due date since when others have been granted the same as the petitioner is working on the post of Time Keeper 1964 and he has not been granted any promotion so far though he is to retire on the same post on 31.01.2004.

(d) To issue directions to the respondents by issuance of a writ of mandamus to give to the petitioner, the scale equivalent to the scale of regular Time Keeper i.e. instead of 445-635 to 515-800, corresponding scale of which are 950-1530, 3050-4590 which are being given to the similarly situated persons on the basis of equal pay for equal work.

(e) Any other order/orders, writ/writs, direction/directions that this Hon'ble Court may deem fit and proper, may also kindly be given; and

(f) Cost of the petition may kindly be awarded.

2. The contention of learned counsel for the petitioner is that he was appointed on the post of Time Keeper on 23.9.1964. He was declared permanent w.e.f. 22.9.1979 vide Annexure-P-3, which is a copy of the Service Book containing this fact. The further contention of learned counsel is that after having served for near about 40 years, the petitioner retired on 21.1.2004, but he was not at all promoted. However, the

employees who are junior to the petitioner and who were serving in the same cadre were promoted. In this regard my attention has been drawn to Annexures-P-9 to P-14 and Annexures-P-35 to P-38.

3. On the other hand, Shri Agnihotri, learned Govt. Advocate has submitted that since the petitioner was serving under the Work-charge Establishment and there is no provision to provide promotion to the employees serving under the Work-charge Establishment, therefore, the petitioner was not promoted.

4. After having heard learned counsel for the parties, I am of the view that this petition deserves to be allowed in part.

5. There is no merit in the contention of learned Govt. Advocate that the employees serving under the Work-charge Establishment, since there is no provision to give promotion to them, they are not entitled for any promotion. There is no merit in the contention of learned Govt. Advocate that employees serving under the Work-charge Establishment are also not entitled for promotion under the Time Bound Promotion Scheme. Shri Shrivastava, learned counsel appearing for the petitioner has submitted that the Time Bound Promotion Scheme is applicable to the employees serving under the Work-charge Establishment. On bare perusal of Annexure-P-7, it is gathered that the respondents are giving promotion under the Time Bound Promotion Scheme to the Drivers serving under Work-charge Establishment. When the promotion under the Time Bound Promotion Scheme is being given to the Drivers of the Work-charge Establishment, then why the petitioner should not be benefited in the same manner. The Supreme Court in the case of <u>Raghunath Prasad</u>

SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Singh v. Secretary, Home (Police) Department, Government of Bihar and others AIR 1988 SC 1033 in para 4 has held as under :-

> "4. Before we part with the appeal, we would like to take notice of another aspect. In course of hearing of the appeal, to a query made by us, learned counsel for the appellant indicated the reason as to why the appellant was anxious to switch over the general cadre. He relied upon two or three communications which are a part of the record where it has been indicated that there is no promotional opportunity available in the wireless organisation. Reasonable promotional opportunities should be available in every wing of public service. That generates efficiency in service and fosters the appropriate attitude to grow for achieving excellence in service. In the absence of promotional prospects, the service is bound to degenerate and stagnation kills the desire to serve properly. We would, therefore, direct the State of Bihar to provide at least two promotional opportunities to the officers of the State Police in the wireless organisation within six months from today by appropriate amendments of Rules. In case the State of Bihar fails to comply with this direction, it should, within two months thereafter, give a fresh opportunity to personnel in the Police wireless organisation to exercise option to revert to the general cadre and that benefit should be extended to everyone in the wireless organisation.

The same principle has been reiterated in the case of Dr. Ms. O.Z. Hussain v. Union of India and others AIR 1990 SC 311. This Court in the case of Smt. Kamla Devi Tiwari v. The State of M.P. and another (W.P.No.9368/2003) decided on 5.1.2005 has held that according to the decision of Raghunath Prasad Singh (supra) the employees are entitled for promotion and the respondents were directed to extend the said benefit in terms of the decision of Supreme Court in Raghunath Prasad Singh (supra).

For Copying fees only

20 (53)

6 Since the Time Bound Promotion Scheme is applicable to the Drivers serving under the Work-charge Establishment, the view of this Court is that the same is also applicable to the petitioner who was serving on the post of Time Keeper and was retired from the said post.

7. Eventually, this petition succeeds in part and the respondents are hereby directed to extend the benefit of Time Bound Promotion Scheme to the petitioner and monetary benefits be paid to him on or before 31.3.2006. It is made clear that if necessary orders in that regard are not issued by the respondents and monetary benefits are not paid to the petitioner on or before 31.3.2006, he shall be entitled to the interest @ 6% per annum on the said amount w.e.f. 1.4.2006.

8. This petition is accordingly allowed to the extent indicated hereinabove with no order as to costs.

Sd/- ...11.05

(A.K.SHRIVASTAVA)
JUDGE

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

TRUE COPY
Head ... High Court of M... Pradesh JABALPUR

शपथ आयुक्त 1789 ... उच्च न्यायालय

18/5/12

True copy

A TRUE COPY

20.5.12

I.L.R. [2009] M. P., 1326
WRIT PETITION
Before Mr. Justice Rajendra Menon
23 January, 2009*

TEJU LAL YADAV ... Petitioner
Vs.
STATE OF M.P. & ors. ... Respondents

Constitution, Articles 14, 16 & 309 - Contingency Paid Employees - *Time Bound Promotion* - *Contingency paid and work charged employees are considered to be forming a common class - The benefit of time bound promotion which is extended to work charged employees is also to be extended to contingency paid employee - Petition allowed.* (Paras 8 & 11)

संविधान, अनुच्छेद 14, 16 व 309 – आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी – समयबद्ध पदोन्नति – आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को समान वर्ग निर्मित करने के लिए विचार में लिया गया – समयबद्ध पदोन्नति का लाभ, जो कार्यभारित कर्मचारियों तक विस्तारित है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तक भी विस्तारित किया गया है – याचिका मंजूर।

Cases referred :

K.L. Asre Vs. State W.P. No.1070/2003(S) decided on 07.11.2005.

Shiv Kumar Dubey, for the petitioner.
Alok Pathak, for the respondents.

ORDER

RAJENDRA MENON, J. :–The petitioner claims to be working in the Government Mahila Polytechnic College, Ghamapur as Hostel Peon. It is claimed that the petitioner was initially appointed on the post of Work Shop Labour in the year 1983 against the vacant and sanctioned post and thereafter, continued to work in the said post. Vide order dated 20th March, 1989 he was regularized in the regular work charged and contingency paid establishment on the post of Hostel Peon. Claiming grant of time bound promotion under the scheme formulated by the State Government vide Annexure P/3 dated 17.03.1999 and modified vide Annexure P/4 dated 27.02.2001, the petitioner sought grant of benefit after completing 12 years of service. However, when representations were made and the same were not considered, the petitioner has filed this petition.

... notice being issued, the respondents have filed a reply and the only ... of the respondents is to the effect that the petitioner is a contingency ... ee, therefore, the scheme contemplated for granting the time bound ... contained in Annexures P/3 and P/4 is not applicable.

... ase of the respondents that the scheme for time bound promotion

... (Jabalpur)

y applicable to employees who are working in the regular establishment and employees of the work charged or contingency paid establishment.

Learned counsel for the petitioner placing reliance on the judgment rendered Bench of this Court in Writ Petition (S) No.1070/2003 *(K.L.Asre vs. State)* d on 07.11.2005, submits that when the work charged establishment Drivers he Time Keepers in the Public Works Department are held entitled for otion under the aforesaid scheme, the petitioner, who is a contingency paid oyee, is also entitled to the same benefits.

In case of *K.L.Asre* (supra), the benefit of time bound promotion is extended employees of Work Charge Establishment in the Public Works Department is so held by the learned Judge in paragraph No.5 of the aforesaid judgment, h reads as under :-

> "On bare perusal of Annexure P/7 it is gathered that the respondents are giving promotion under the Time Bound Promotion Scheme to the Drivers serving under Work-charge Establishment. When the promotion under the Time Bound Promotion Scheme is being given to the Drivers of the Work Charge Establishment, then why the petitioner should not be benefited in the same manner. The Supreme Court in the case of *Raghunath Prasad Singh vs. Secretary, Home (Police) Department, Government of Bihar and others,* AIR 1988 SC 1033 in para 4 has held as under:-
>
> "4. Before we part with the appeal, we would like to take notice of another aspect. In course of hearing of the appeal, to a query made by us, learned counsel for the appellant indicated the reason as to why the appellant was anxious to switch over the general cadre. He relied upon two or three communications which are a part of the record where it has been indicated that there is no promotional opportunity available in the wireless organization. Reasonable promotional opportunities should be available in every wing of public service. That generates efficiency in service and fosters the appropriate attitude to grow for achieving excellence in service. In the absence of promotional prospects, the service is bound to degenerate and stagnation kills the desire to serve properly. We would, therefore, direct the State of Bihar to provide at least two promotional opportunities to the officers of the State Police in the wireless organization within six months from today by appropriate amendments of Rules. In case the State of Bihar fails to comply, with this direction, it should within two months thereafter, give a fresh opportunity to personnel in the Police wireless organization to exercise option to report to the general cadre and

that benefit should be extended to everyone in the wireless organization."

The same principle has been reiterated in the case of *Dr.Ms.O.Z.Hussain vs. Union of India and others*, AIR 1990 SC 311. This Court in the case of *Smt.Kamla Devi Tiwari vs. The State of M.P. and another* (W.P. No.9368/2003) decided on 05.01.2005 has held that according to the decision of *Raghunath Prasad Singh* (supra) the employees are entitled for promotion and the respondents were directed to extend the said benefit in terms of the decision of Supreme Court in *Raghunath Prasad Singh* (supra).

6. Since the Time Bound Promotion scheme is applicable to the Drivers serving under the Work Charge Establishment, the view of this Court is that the same is also applicable to the petitioner who was serving on the post of Time Keeper and was retired from the said post."

(Emphasis supplied)

6. Apart from the above, it is seen that the petitioner is working in Polytechnic College and is said to be a contingency paid employee. Under M.P. Education Department (Technical Branch) Contingency Paid Employ Recruitment and Conditions of Service Rules, 1978, a contingency paid emplo is defined under Rule 2(b) to mean a person employed for full time in an offic establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged "Office Contingencies" but it excludes such of the employees who are emplo for certain periods only in the year. In the aforesaid Rules of 1978, the categoriza of employees is done under Rule-6 and the employees are classified into categories i.e. permanent and temporary. Under Sub-rule 2 of Rule-6, it is provi that on completion of 15 years of continuous service the contingency paid employ shall be eligible for attaining the status of permanent work charged or continge paid employee. The similar provisions are made in the M.P. (Work Charged Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979 wherein the perman employee is defined under Rule 2(c) to mean a contingency paid employee or work charged employee who has completed 15 years of service or more on after 1st January, 1974.

7. The complete reading of these Rules indicates that a contingency pa employee attaining the permanent status and a work charged employee attaini the permanent status are treated to be similar in all respects for the purpose granting them pension and revision of pay scales under the M.P. Work Charg and Contingency Paid Employees Revision of Pay Rules, 1990 and under the M.P. (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979,

8. Considering the fact that under the statutory rules also the contingency pa

the work charged employees are considered to be forming a common class. re is no reason why the benefit of time bound promotion which is extended to work charged employees and why the judgment rendered in case of *K.L.Asre* ra) be not made applicable in the case of the present employee also who has ined the status of a permanent work charged or contingency paid employees entitled to various benefits in the matter of revision of pay and pension in ntical manner.

A perusal of the Policy as contained in Annexure P/3 further indicates that en though the policy speaks about granting Krammanoti under the scheme to ployees in the regular establishment, but by Clause (13) and (14) of the Scheme, Government has extended the benefit of Krammanoti to vehicle drivers working the work charged and contingency paid establishment. A perusal of Clauses 3) and (14) clearly indicates that the benefit of Krammanoti after completing 12 ars and 24 years of service is made applicable to employees in the work charged nd contingency paid establishment.

0. As far as work charged and contingency paid employees are concerned, heir service conditions are governed by the same rules namely the Work Charged and Contingency Paid Employees Recruitment Rules, applicable to various Departments and the Work Charged and Contingency Paid Employees Pension Rules 1979 and the Work Charged and Contingency Paid Employees Revision of Pay Rules 1990. For the purpose of recruitment, appointment, pay revision and grant of pensionary benefits, the work charged and contingency paid employees constitute a common class and their terms and conditions of employment are governed by identical set of rules. It is, therefore, clear that for the purpose of recruitment, appointment, grant of pension and revision of pay scales, work charged and contingency paid employees are treated similarly and a separate set of rules, different from the one applicable in the regular establishment, govern their terms and conditions of employment. The work charged and contingency paid employees constitute a common class and, therefore, this class of employees are entitled to similar treatment in all respects, deviation being permissible on justifiable grounds and reasons. In the present case, the benefit of time bound promotion under the scheme – Annexure P/3 and P/4, is extended to vehicle drivers working in the work charged and contingency paid establishment, as per the policy itself.

11. The principles laid down in the case of *Shri K.L. Asre* (supra) has been made applicable to time keepers, working in the work charged and contingency paid establishment. If time keepers and drivers in the work charged establishment are entitled to promotion under the time bound scheme, there is no reason as to why the said benefit be not extended to other employees constituting the same class in the work charged and contingency paid establishment. The policy is made applicable to drivers of this establishment and the reason for not making the said

policy applicable to other categories of the work charged and contingency pa[illegible] establishment is not indicated in the return. No reason is given as to why a differ[illegible] policy is being adopted in the case of other employees in the work charged and contingency paid establishment and the benefit granted to drivers in the said establishment is not extended to other employees like the petitioner. Respondents being a "State" has to give similar benefit to employees similarly situated and forming a common class. They may be justified in granting some additional benefi[illegible] to some of the employees in comparison to others, but the justification and reason[illegible] for such a classification has to meet the test of Article 14 of the Constitution a[illegible] the decision has to be reasonable, fair and justified by cogent reasons and releva[illegible] considerations. Except for contending that the Policy is not applicable to employe[illegible] working in the work charged and contingency paid establishment, no justificati[illegible] is forthcoming from the respondents with regard to further classification amon[illegible] the employees working in the work charged and contingency paid establishme[illegible] with regard to implementation of the Policy – Annexure P/3 and P/4. When [illegible] employees working in the work charged and contingency paid establishm[illegible] constitute a common class, all benefits which are extended to one set of employe[illegible] namely drivers as per the policy and the time keepers in the light of the judgm[illegible] in the case of *K.L. Asre* (supra), has to be granted by the respondents to [illegible] present petitioners also. In the absence of proper justification for adopti[illegible] different policy and cogent reason given justifying the reasonableness in [illegible] classification and differentiation done fulfilling the requirement of Article 14 [illegible] the Constitution, discrimination cannot be permitted. Parity in employment [illegible] required to be maintained and, therefore, keeping in view the circumstances a[illegible] the action of the respondents in adopting a pick and choose method violative [illegible] Article 14 of the Constitution in the case of employees who form a homogeno[illegible] class, the action discriminatory in nature cannot be upheld by this Court.

12. Keeping in view the aforesaid, the respondents are directed to extend th[illegible] benefit of promotion in accordance with the aforesaid scheme to the petitione[illegible] and after evaluating his case in accordance with the requirements of the sa[illegible] scheme, grant benefit to the petitioner. In case the petitioner is found entitled the[illegible] necessary orders in this regard be passed within a period of 03 months.

13. The petition is, accordingly, allowed and disposed of.

Petition allowed.

ANNEXURE

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

क्रमांक एफ 18-83/2008/बयालीस(1) भोपाल, दिनांक मार्च, 2012

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-5-4/1/वैआप्र/98, दिनांक 27/29-3-2001 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले केवल वाहन चालकों को क्रमोन्नति योजना के अन्तर्गत क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। श्री तेजूलाल यादव, मजदूर एवं श्री नर्मदा प्रसाद कुशवाह, चौकीदार शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारियो की श्रेणी में हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त दिशा निर्देशों के तहत् क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया।

2/ याचिकाकर्ता श्री तेजूलाल यादव (मजदूर) एवं श्री नर्मदा प्रसाद कुशवाह, चौकीदार शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर, जो कि नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी है, द्वारा 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् राज्य शासन की समयबद्ध पदोन्नति की योजनानुसार, पदोन्नति न मिलने के कारण क्रमशः याचिका क्रमांक 11507/2007 एवं याचिका क्रमांक:11505/2007 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य दायर की गई, जिसमें दिनांक 23 जनवरी, 2009 को पारित मान. उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार याचिकाकर्ता को आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी होने के कारण समयबद्ध क्रमोन्नति न दिये जाने के निर्णय को सही न मानते हुए योजनांतर्गत पात्रतानुसार पदोन्नति देते हुए समस्त लाभ तीन माह के भीतर देने के निर्देश दिये हैं।

3/ राज्य शासन के क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, विभाग द्वारा उपरोक्त न्यायालयीन निर्णय के विरूद्ध रिट अपील क्र. 966/2009 दायर की गई जिसे मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2009 को खारिज किया गया।

4/ प्रकरण में विभाग द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का निर्णय लिया गया एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय मे दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) क्र. 14582/2010 दायर की गई उक्त अपील को दिनांक 27.09.2010 को खारिज की गई।

5/ प्रकरण में न्यायालीन निर्णय का पालन न होने के कारण अवमानना की स्थिति निर्मित हुई है एवं सुनवाई दिनांक 26 मार्च, 2012 को निर्धारित है।

अतः राज्य शासन द्वारा प्रकरण क्रमॉक:11507/2007 एवं क्रमांक 11505/2007 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय के पालन में श्री तेजूलाल यादव, मजदूर एवं श्री नर्मदा प्रसाद कुशवाह, चौकीदार, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर को क्रमशः दिनांक 19-04-99 एवं दिनांक 01-10-2000 से क्रमोन्नति का लाभ प्राचार्य के

TRUE COPY
Dr. Anuvad Shrivastava
Advocate

48